लोकतंत्र

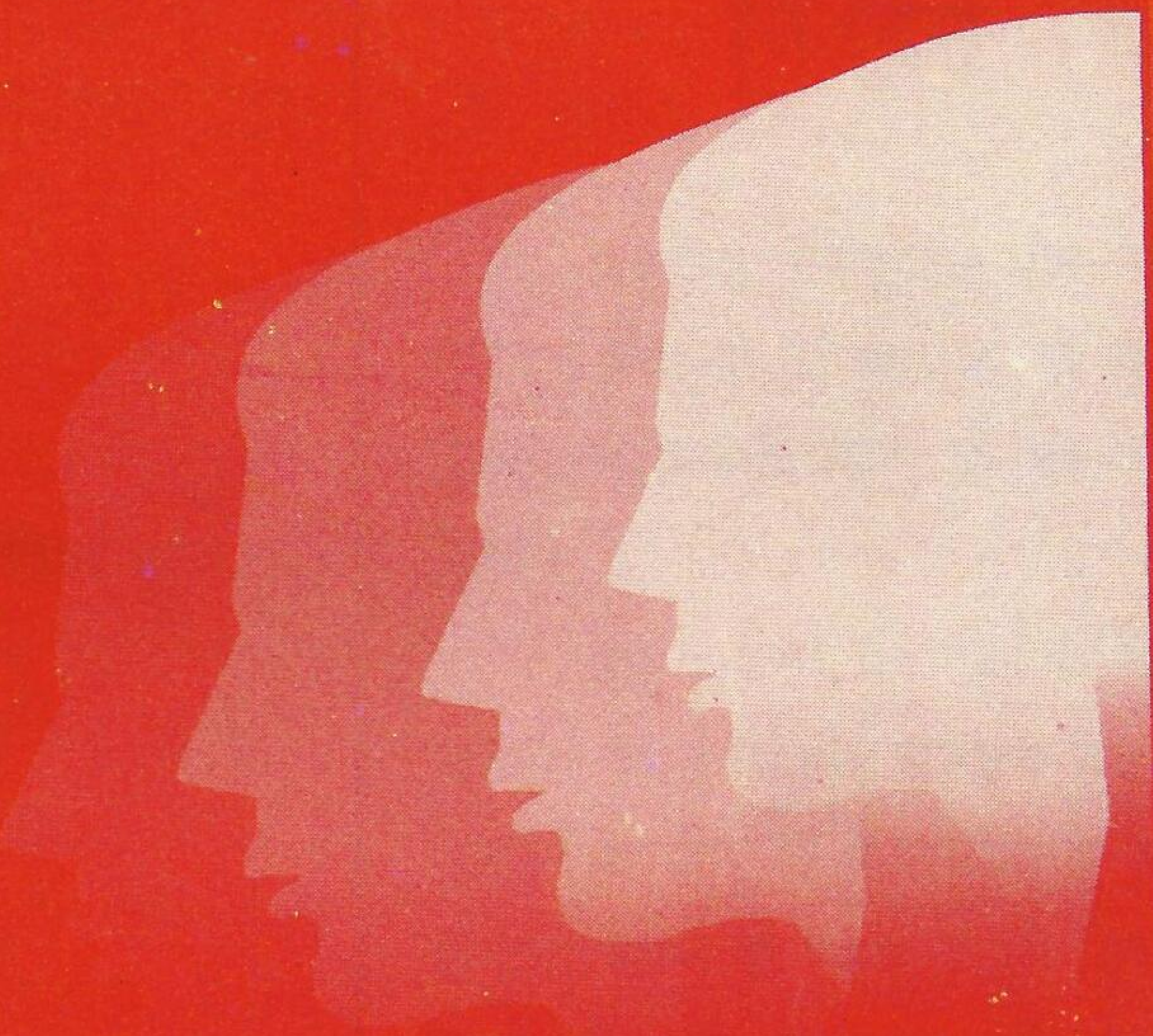

"मजदूरों की नहीं तो यह समस्त लोकतांत्रिक शक्तियों की लड़ाई है"

- दत्तोपंत ठेंगड़ी

प्रकाशक :
लोकहित प्रकाशन
संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर,
लखनऊ – २२६ ००४

तृतीय संस्करण
दत्तात्रेय जयन्ती (मार्गशीर्ष शुक्ल १५)
सम्वत् २०६०
८ दिसम्बर, २००३

मूल्य : रु. ६.००

मुद्रक :
नूतन आफसेट मुद्रण केन्द्र
संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर,
लखनऊ – २२६ ००४

निवेदन

प्रख्यात चिन्तक और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी ने अपनी आयु के ६० वर्ष पूर्ण किये।

इस अवसर पर देश भर में उनके सत्कार के कार्यक्रम सम्पन्न हुए जिनमें उन्होंने आज देश में लोकतन्त्र को पुनः समाप्त करने के षड्यन्त्र की विस्तार से चर्चा की और साम्राज्यवादी दुष्चक्र से देश के सार्वभौमत्व व स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु राष्ट्रभक्त नागरिकों से अपील की।

आशा है कि सामयिक मार्गदर्शन की दृष्टि से यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।

मकर संक्रांति

सन् १९८२

– प्रकाशक

अतिशय स्नेह के समक्ष नतमस्तक

आज के इस अवसर पर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए यह मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा सभाएँ होती हैं, हम भाषण भी देते हैं किन्तु आज का अवसर कुछ दूसरे ढंग का है जिसमें आप लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं। ऐसे सत्कार सभा में क्या बोलना चाहिए इसका मुझे पता नहीं। क्योंकि जिस अखाड़े से मैं आया हूँ उस अखाड़े में कोई किसी का सत्कार करता ही नहीं, सभी लोग कार्य करते जा रहे हैं– २० साल, ४० साल, ५० साल– लेकिन कोई किसी का सत्कार नहीं करता। इसके कारण ऐसे अवसर पर किस ढंग से बोलना चाहिए– इस असमंजस में मैं हूँ। दूसरी बात– मेरे विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे गये हैं। यह तो हमारे साथियों का प्रेम है। प्रेम यह मेग्नीफाइंग ग्लास के समान होता है। मेग्नीफाइंग ग्लास में छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है। वैसे ही प्रेम के कारण मेरे सहकारियों को मेरा छोटा काम भी बहुत बड़ा मालूम होता है। भारतीय मजदूर संघ आज एक विशाल स्वरूप धारण कर चुका है यह बात ठीक है, लेकिन यह मेरे कारण है यह कहना केवल अतिशयोक्ति ही नहीं तो यह गलत होगा। मैं कई नेताओं से, सार्वजनिक जीवन में यह शिकायत सुनता रहता हूँ कि जनता कृतघ्न है– हम देश के लिए कितने बर्बाद हुए हैं लेकिन जनता ने उसका कुछ भी महत्त्व नहीं माना– ऐसी शिकायत मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन मेरे विषय में कुछ उल्टा मामला ही मालूम होता है। मेरे जन्म–पत्री में शनि व मंगल ऐसे स्थान पर बैठा है, कि काम तो मेरे सहकारी करते रहते हैं और काम में यदि यश प्राप्त हुआ, तो उसका श्रेय वे मेरी ओर खिसका देते हैं। काम में यदि असफलता हुई तो उसका अपयश वे स्वयं लेते हैं। इसके कारण जो मेरा बैंक एकाउण्ट देखता है उसको केवल श्रेय ही श्रेय दिखाई देता है, लेकिन यह हमारे द्वारा जमा किया हुआ श्रेय नहीं है। हमारे साथियों द्वारा जमा किया हुआ यश है। लेकिन इसके कारण एक आभास होता

है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है।

यह व्यक्ति का नहीं– सिद्धान्त का सम्मान है

वैसे अपने देश में यह एक पद्धति है कि प्रेम के कारण किसी को भी अति श्रेष्ठ बताना, जो वास्तव में वास्तविकता से दूर है। एक छोटा–सा प्रसंग याद आता है– पूज्य महात्मा जी गुरुदेव के निमंत्रण पर शांति निकेतन कुछ दिन के लिए गये थे। एक विदेशी पत्रकार ने कुछ प्रश्न दोनों से अलग–अलग पूछे। उसमें से एक प्रश्न यह था कि आज का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है ? पहले महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने जवाब दिया– 'मैं और किसी को नहीं जानता– गुरुदेव के अतिरिक्त। यानी सबसे श्रेष्ठ कवि गुरुदेव हैं। वही प्रश्न गुरुदेव से पूछा। उन्होंने जो उत्तर दिया वह ध्यान में रखने लायक है। उन्होंने कहा कि निसर्ग को सर्वश्रेष्ठ मान्य नहीं है– कोई श्रेष्ठ हो सकता है किन्तु सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो प्रेम के कारण, एक पद्धति के कारण अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है– यह भी ध्यान में रखना चाहिए।

हम ही किसी पत्थर को सिन्दूर लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि यह हनुमान् जी हैं और उसके सामने हम ही प्रणाम करते हैं। ऐसा ही कार्यकर्त्ताओं का कुछ इस अवसर पर हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। यह जो सारा उपक्रम हुआ है इसमें कई लोगों ने सहयोग दिया। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं ने तो काम किया ही है, उसके अलावा भी जिनका मजदूर क्षेत्र से सीधा सम्बन्ध नहीं, लेकिन जिनके मन में यह विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ केवल ट्रेड यूनियन नहीं है जो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख माध्यमों में से एक माध्यम यह भारतीय मजदूर संघ है, ऐसा विश्वास जिनके मन में है ऐसे देशभक्त नागरिक बन्धुओं ने भी इसमें सहयोग दिया है। मैं हृदयपूर्वक आप सब बन्धुओं का धन्यवाद करता हूँ– आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यह व्यक्ति का सम्मान नहीं है तो एक संगठन और एक सिद्धांत–एक आदर्श– इसके प्रतिनिधि के रूप में ही यह सम्मान हो रहा है। अतः सभी बन्धुओं का जिन्होंने इस कार्य में 'पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम्' सहयोग दिया है– सभी के प्रति अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

श्रमिक जगत् पर कुठाराघात

वैसे देखा जाये तो सत्कार समारोह यह आनन्द का ही विषय होना

चाहिए। लेकिन जो परिस्थितयाँ आज देश में और मजदूर क्षेत्र में हैं, उनको देखते हुए किसी को भी आनन्द होना, बड़ा कठिन काम है। देश की भी स्थिति, मजदूरों की भी स्थिति आज बहुत ही शोचनीय है। जहाँ तक मजदूर क्षेत्र का सम्बन्ध है हम सब लोग जानते हैं कि इस समय सरकार ने एक बहुत बड़ा हमला मजदूर आन्दोलन पर किया हुआ है। अभी–अभी जो आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून पास हुआ, वह मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को छीनने वाला है और इस तरह एक कुठाराघात मजदूर आन्दोलन पर सरकार ने किया है। इतना बड़ा आघात करने की आवश्यकता क्या थी ? इसका विचार आप सबने किया, तो आपको आश्चर्य होगा कि पिछले दो साल में कोई भी ऐसी अभूतपूर्व घटना नहीं हुई थी कि जिसके कारण यह अभूतपूर्व अनोखा कदम उठाने की आवश्यकता किसी भी समझदार सरकार को प्रतीत हो।

पिछले दो साल में उत्पादन की मात्रा वही रही जो हमेशा रहती थी। नष्ट हुए श्रम–दिनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं थी, हड़तालों की संख्या उतनी ही थी जितनी हमेशा रहती है। कोई भी अनोखी बात नहीं हुई थी कि जिसके कारण यह हमला करना उचित था; तो भी यह हमला हुआ है। इस तरह का हमला करने की हिम्मत सरकार को क्यों हुई– इसका गम्भीरता से सभी लोगों को विचार करना आवश्यक है।

सरकारी कुप्रचार

पहली बात यह ख्याल में आती है कि पिछले ३४ साल में सरकार ने मजदूरों के विषय में तरह–तरह की गलतफहमियाँ फैलाने का कार्य जारी रखा है। डा. गौबेल्स की सिद्धान्त था कि कोई भी झूठ बात आप एक सौ बार दोहराइये– तो बार–बार कहने के कारण सुनने वाले को यह लगेगा कि यह सच्चाई है। भारत सरकार ने इसी का प्रयोग किया है और इसके कारण मजदूरों के बारे में प्रेम रखने वाले लोग भी मजदूर आन्दोलनों के विषय में काफी गलतफहमी रखते हैं। गलत प्रचार तो तरह–तरह का है किन्तु केवल १–२ उदाहरण मैं आपको दूँगा। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि भाई मजदूर गैर–जिम्मेवार है। वास्तव में उसी समय सरकार यह भी कहती है कि इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि हुई। अरे ! मजदूर अगर गैर जिम्मेवार है तो उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी ? दो परस्पर विरोधी वक्तव्य सरकार के लोग एक ही समय में करते रहते हैं। फिर भी लोगों में एक बात फैल गयी है कि मजदूर गैर जिम्मेवार है।

वायुमण्डल का सम्पूर्ण समाज पर स्वाभाविक परिणाम

कभी–कभी बात करने का मौका आता है, किसी ने कहा कि तुम्हारे मजदूर बड़े गैरजिम्मेवार हैं। हमने प्रतिप्रश्न किया कि हमारे देश में ऐसे और कितने हैं जो लोग गैर जिम्मेवार नहीं हैं इसकी सूची दीजिये। वास्तव में मजदूर क्षेत्र यह समाज से कटा हुआ क्षेत्र नहीं है। सम्पूर्ण समाज में जो वायुमण्डल होगा उसका स्वाभाविक परिणाम मजदूर क्षेत्र पर भी होता है, जैसे विद्यार्थी क्षेत्र पर भी होता है, हर क्षेत्र पर होता है। सम्पूर्ण समाज में वायु–मण्डल यदि स्वार्थ का, गैर जिम्मेवारी का, राष्ट्रभक्ति–विहीनता का होगा तो केवल एक किसी क्षेत्र में– यह चाहे मजदूर क्षेत्र ही क्यों न हो, दूसरा वायुमण्डल मिलना चाहिए ऐसी अपेक्षा रखना एक अवास्तविक बात है। आज समाज का वायुमण्डल क्या है यह देखना चाहिए। किसी भी समाज में, जो मनोवैज्ञानिक वायुमण्डल बनता है, उसमें पहल करने का काम हमेशा नेताओं का हुआ करता है क्योंकि नेताओं का जैसा व्यवहार रहेगा उसी का अनुकरण बाकी लोग करते हैं।

आज जिनको देश का शीर्षस्थ नेता माना गया है, वे लोग इस देश के सर्वोच्च मंच पर– पार्लियामेंट में– एक दूसरे को गाली–गलौज कर रहे हैं, एक–दूसरे पर उछल रहे – जो ज्यादा प्रगतिशील व क्रान्तिकारी हैं वे एक–दूसरे पर जूते भी निकाल रहे हैं– यह समाचार अगर हमारे मजदूर व विद्यार्थी हर दिन समाचारपत्र में पढ़ते हैं और फिर उनसे यह अपेक्षा की जाये कि नेता तो अनुशासन विहीन रहें और बाकी लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए– तो यह गलत बात होगी।

गैर जिम्मेवार वायुमण्डल के लिए नेता दोषी

यह ठीक है कि हम राष्ट्रभक्त हैं हम उत्पादन में बाधा लाना नहीं चाहते, अनुशासन से रहना चाहिए ऐसी हमारी इच्छा है। जिम्मेवारी की भावना का प्रचार हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं– लेकिन उसको सीमित यश प्राप्त होता है क्योंकि समाज में फैला हुआ अनुशासनहीनता का व गैर जिम्मेवारी का वायुमण्डल है, जिसके लिए वास्तव में जिम्मेवार नेता हैं। इसके लिए यदि कोई उपाय–योजना होगी वह यही हो सकती है कि आज जिनको समाज का नेता माना जाता है उनका व्यवहार आदर्श रहना चाहिए या जिनका व्यवहार आदर्श है ऐसे लोगों को नेता मानने की आदत समाज को लगनी चाहिए। दोनों में से

एक बात जब तक नहीं होती तब तक यह वायुमण्डल दुरुस्त नहीं हो सकता। इतना खराब वायुमण्डल होते हुए भी हिन्दुस्थान का मजदूर उत्पादन बढ़ा रहा है, काम बराबर कर रहा है और इतना ही नहीं तो जब कभी देश पर संकट आता है– १९६२ में चीन के आक्रमण के समय, ६५ में पाकिस्तान के आक्रमण के समय, ७१ में बांग्लादेश की लड़ाई के समय, मजदूरों ने ज्यादा घण्टे काम किया है। अतिरिक्त भत्ता न लेते हुए, स्वयं गरीब रहते हुए सुरक्षा कोष में पैसा दिया। स्वयं दुबले–पतले रहते हुए ब्लडबैंक में अपना खून जमा किया है, जवान के नाते लड़ने के लिए अपने नाम दिये हैं, और इतना ही नहीं तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि १९६५ की लड़ाई के समय, हमारे कुछ कार्यकर्त्ताओं ने, पाकिस्तान की सीमा पर अपनी युद्ध–सामग्री बचाने के लिए, हमारे कुछ रेल कर्मचारी बन्धुओं ने अपनी जान भी कुर्बान की है। यह सारा होते हुए भी आज आम आदमी के दिमाग में यह बात बैठी है कि सबसे ज्यादा गैर जिम्मेवार मजदूर है तो इसका कारण एक ही है कि सरकार की ओर से लगातार यह प्रचार हो रहा है। इस तरह के गलत प्रचार के प्रतिवाद करने का काम, आज जनता को विश्वास में लेकर मजदूरों की बात उनको समझाने का काम भारतीय मजदूर संघ के पूर्व काम करने वाले किसी भी यूनियन ने नहीं किया, इसी के कारण यह सारा गलत प्रचार बड़ा प्रभावी हुआ है।

उत्पादन की कमी के अनेक कारण

दूसरा उदाहरण आपके सामने देता हूँ। सरकार ने निरन्तर यह प्रचार किया कि उत्पादन में जो कुछ भी कमी होती है उसका प्रमुख कारण मजदूरों की हड़तालें हैं और दूसरा प्रचार किया कि मजदूरों का पैसा बढ़ने के कारण, मँहगाई बढ़ती है। भारतीय मजदूर संघ ने इन दोनों बातों के विषय में प्रारम्भ से जनता को सुशिक्षित करने का प्रयास किया था कि यह दोनों आरोप गलत हैं। आज सौभाग्य से एक निष्पक्ष संस्था जिसका नाम है Indian Institute of Public Administration जिसने पिछले जुलाई–अगस्त महीने में, इन्हीं दोनों विषयों का अध्ययन व सर्वेक्षण किया और उन्होंने अपने निष्पक्ष निष्कर्ष प्रकाशित किये हैं। हमारे लिए यह आनन्द का विषय है कि भारतीय मजदूर संघ ने प्रारम्भ से जो प्रतिपादन किया था वह और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निष्कर्ष दोनों ही एक जैसे हैं। इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट कहा है कि उत्पादन में जो घट होती है उसके लिए मजदूरों की हड़तालें तो एक नगण्य

कारण है, वास्तव में उत्पादन में घट आने के और भी बड़े कारण हैं। वे कारण उन्होंने बताये कि अव्यवस्था, कच्चा माल समय पर न मिलना, मशीनरी का खराब हो जाना, बिजली की कमी व उसकी रुकावट, बाजार की गलत पालिसी रहना, निर्यात की सुविधाएँ उपलब्ध न होना– यह बड़े कारण हैं।

मँहगाई बढ़ने के तीन कारण

मँहगाई बढ़ने के तीन प्रमुख कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से कहे। एक घाटे की अर्थव्यवस्था, दूसरा काला पैसा और तीसरा अनियंत्रित लाभांश और ब्याज। हम सब लोग जानते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में है और डिफीसिट फाइनैन्सिग की मात्रा निरन्तर बढ़ाने का काम स्वयं सरकार करती है। जो काला पैसा कमाते हैं उनको नजदीक के खम्भे पर फाँसी दी जायेगी, ऐसा स्व. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था लेकिन अभी पिछले साल काला पैसा कमाने वाले को सरकार ने अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है। धारक बांड स्कीम निकाल कर उनको कहा है कि और काला पैसा कमाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप काला पैसा कमाते जाइये, उसको सफेद करने का काम भारत सरकार करती रहेगी; इस तरह का उनको आश्वासन दिया है, उनकी पीठ थपथपाई है। लाभांश व ब्याज का नियंत्रण करने की हिम्मत भारत सरकार की नहीं है, यह बात तो साफ है। याने जो प्रमुख कारण मँहगाई बढ़ने के हैं, उसके लिए जिम्मेवार स्वयं सरकार है लेकिन बलि का बकरा मजदूरों को बनाया जाता है। हालाँकि इंस्टीट्यूट के निष्कर्ष के अनुसार मजदूरों का बढ़ा हुआ पैसा जिसका बहुत थोड़ा असर नगण्य प्रभाव महँगाई पर होता है।

एक गलतफहमी

सरकार के गलत प्रचार के कारण, अखण्ड प्रचार के कारण सुशिक्षित लोगों के मन में भी, ये दोनों गलतफहमियाँ जमकर बैठ गयी हैं। इसका परिणाम क्या होगा ? ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने जिस तरह समाज से सम्पर्क रखना चाहिए था उस तरह नहीं रखा, इसके कारण, जब कभी सरकार के साथ संघर्ष होता है, मजदूरों की बात आम जनता के ख्याल में नहीं आती। वास्तव में दृश्य तो ऐसा उपस्थित होना चाहिए कि मजदूर और आम जनता एक तरफ, अकेली सरकार एक तरफ। किन्तु ऐसा दृश्य निर्माण होता है कि मजदूर अकेला एक तरफ और आम जनता सरकार के साथ खड़ी है। मजदूर अकेला पड़ता है

सरकार अकेली नहीं पड़ती। आम जनता को विश्वास में लेकर खुद से अपनी बात समझाने का काम भारतीय मजदूर संघ के पूर्व यूनियनों ने नहीं किया इसके कारण सरकार का हौसला बढ़ गया है। दूसरी बात, जिस देश में मजदूर एकता कायम हुई है, वहाँ मजदूरों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि सरकार को भी उनके कहने के अनुसार विचार करना पड़ता है। उनका प्रभाव रहता है। पोलिटिकल यूनियनइज्म के कारण. एक-एक कारखाने में, एक-एक उद्योग में चार-चार पाँच-पाँच मजदूर संघ खड़े हो जाते हैं। आज भी हमारे देश में, हर जगह चार, पाँच, छह यूनियनें खड़ी हम देखते हैं इसका कारण यही है, पोलिटिकल यूनियनइज्म। यदि राजनैतिक मजदूर संघों के सिद्धान्त को स्वीकार किया, तो हर एक कारखाने में, उतनी यूनियनें बनने की गुंजाइश हो जायेगी जितनी राजनैतिक पार्टियाँ हिन्दुस्थान में हैं। इससे मजदूर बँट जाता है उसकी सामूहिक सौदे की ताकत और संघर्ष करने की शक्ति घट जाती है। इसका लाभ सरकार उठा सकती है।

गैर राजनीतिक आधार पर मजदूर संगठन आवश्यक

दुनिया का अनुभव यदि हम देखें, कई देशों में राजनैतिक मजदूर संघवाद चल रहा है। यह सिद्धांत कम्युनिस्टों का है, लेकिन बाकी लोगों ने भी उनका अंधानुकरण किया है। पश्चिम में जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी में पोलीटिकल यूनियनइज्म के कारण मजदूर बँट गया और इसके कारण वहाँ मजदूरों की वास्तव में जितनी शक्ति है उसका सरकार पर प्रभाव नहीं है। उसके उल्टे जिस देश को पूँजीवाद का अड्डा माना गया है, जहाँ पूँजीपतियों की ताकत बहुत ज्यादा है, वहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में भारतीय मजदूर संघ के ही समान गैर राजनैतिक विशुद्ध मजदूर यूनियन के आधार पर मजदूरों के संगठन खड़े हैं। इसके कारण एक उद्योग में एक ही यूनियन है। यह बात ठीक है कि हर एक मजदूर जैसे मजदूर हैं, वैसे नागरिक भी हैं और नागरिक के नाते किसी भी पार्टी में काम करना या न करना उनका अधिकार है। लेकिन जहाँ तक यूनियन का सवाल है, उसे राजनीति में न लाया जाये। अलग-अलग राजनैतिक दलों में होते हुए भी, सभी मजदूर अपने हित के लिए एक यूनियन के मंच पर काम करते हैं। इस तरह की यूनियन अमेरिका में हैं और इसके कारण हर एक उद्योग में एक ही यूनियन है और अपनी एक-एक यूनियन को लेकर अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर बना है। अपनी एकता के कारण जो देश वास्तव में पूँजीवाद का

गढ़ माना जाता है, उस अमेरिका में, मजदूरों की ताकत इतनी बढ़ी हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी, जिसकी बहुत ज्यादा शक्तियाँ हुआ करती हैं, कोई भी नीति तय करते समय केवल औद्योगिक और मजदूरों की नीति ही नहीं तो विदेश नीति तय करते समय भी दस बार सोचना पड़ता है कि इस नीति के बारे में अमेरिका के मजदूरों की प्रतिक्रिया क्या होगी ? इसका प्रभाव विशुद्ध ट्रेड यूनियनइज्म के कारण पूँजीवाद के अड्डे में मजदूरों ने निर्माण किया है।

जैसे पूँजीवादी देश का मैंने उदाहरण दिया, हम साम्यवादी देशों का भी विचार करें। राजनैतिक यूनियनइज्म कम्युनिस्टों का ही सिद्धान्त है। लेकिन जहाँ–जहाँ कम्युनिस्टों का शासन आया, वहाँ–वहाँ मजदूरों ने इस सिद्धांत का विरोध किया है। रूस में भी हड़तालें होती रही हैं, पिछले साल भी हुईं। हम जानते हैं, किस तरह १९५३ में पूर्वी जर्मनी में, १९५६ में हंगरी में, १९६८ में चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ के मजदूरों ने राजनैतिक यूनियनइज्म का विरोध करते हुए कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में बगावत की थी, यह इतिहास हमारे सामने है। अभी–अभी डेढ़ साल पहले दूसरा एक कम्युनिस्ट शासित देश पोलैण्ड, वहाँ के मजदूरों ने कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ विद्रोह किया है। विद्रोह करते समय उनकी सर्वप्रथम माँग यही थी कि हमें स्वतन्त्र गैर राजनीतिक मजदूर संघ बनाने का अधिकार होना चाहिए। वहाँ इस लड़ाई में सारे मजदूर एक हैं। वहाँ तानाशाही है तो भी इस संघर्ष में मजदूरों की विजय हुई, सरकार की हार हुई और पोलैंड के अन्दर मजदूर इतना प्रभावी हो चुका है, कि आज आपने अखबार में यह पढ़ा होगा कि वे लोग अपनी माँगों को लेकर जब खड़े हुए तो सरकार को वहाँ मार्शल–ला लाना पड़ा। याने बहुत बड़ी ताकत वहाँ खड़ी हुई है। इतनी सख्ती करने पर भी कम्युनिस्टों की नहीं चल रही है। वहाँ भी स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन के आधार पर मजदूरों ने इतनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का सिद्धांत, विशुद्ध, गैर राजनीतिक ट्रेड यूनियनइज्म किस तरह से मजदूरों को प्रबल बना सकता है यह बात हमारे ख्याल में आ सकती है। दुर्भाग्य से, हमारे यहाँ राजनैतिक यूनियनइज्म चल रहा है, मजदूर बँट गया है, संघर्ष की उसकी ताकत कम हो गयी है और इसके कारण उस पर हमला करने में सरकार को संकोच नहीं होता।

राष्ट्रहित की चौखट में मजदूर–हित : यह ध्येय

आज की जो परिस्थिति आयी इसमें यह तो आनन्द की बात है कि यह

इतना भीषण संकट है यह समझ कर आज हिन्दुस्थान की सभी ट्रेड यूनियनें केवल इंटक को छोड़कर, एक मंच पर आ गयी हैं। नेशनल कम्पेन कमेटी के नाम से, उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। उस संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में देश में जगह–जगह तरह–तरह के कार्यक्रम हुए। पिछले २३ नवम्बर को दिल्ली में मजदूरों का एक विशाल प्रदर्शन पार्लियामेंट के सामने हुआ जिसमें १५ लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया था; और आने वाली १६ जनवरी को अपना विरोध प्रकट करने के लिए हिन्दुस्थान के सभी मजदूर एक दिन सांकेतिक हड़ताल पर जाने वाले हैं। यह एकता का दृश्य निर्माण हुआ, यह तो आनन्द की बात है। किन्तु इसी अवसर पर अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको यह सोचना चाहिए, कि वास्तव में यदि हम एकता चाहते हैं तो राजनैतिक यूनियनइज्म को छोड़कर जनरल ट्रेड यूनियन कहना उचित होगा या नहीं होगा, इस बारे में पुनः विचार करना चाहिए। और यदि पुनः विचार करते हुए सभी केन्द्रीय मजदूर संगठन यह निश्चय करते हैं, कि वे राजनैतिक यूनियनइज्म को छोड़ देंगे, किसी भी राजनैतिक दल के निमित्त काम नहीं करेंगे, केवल मजदूरों का ही हित, राष्ट्र हित के चौखट के अन्तर्गत मजदूरों का हित, यह एक ही ध्येय रखते हुए काम करेंगे, ऐसा यदि पाँचों संगठन निश्चय करते हैं, तो मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि उस अवस्था में, सबसे प्रथम भारतीय मजदूर संघ स्वयं अपने को समाप्त करने के लिए तत्पर है। क्योंकि हम संस्थागत हित को लेकर कार्य नहीं कर रहे। राष्ट्र और मजदूरों के हित के लिए हमारा काम है और इस दृष्टि से हम विसर्जित होने के लिए तत्पर रहेंगे यह आश्वासन मैं इस समय दे सकता हूँ।

आर्थिक क्षेत्र की सभी घटनाओं के पीछे सूत्र एक

लेकिन यह देखना चाहिए कि इसी समय यह हमला क्यों ? जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले दो साल में कोई अभूतपूर्व घटना नहीं हुई जिसके कारण इसकी आवश्यकता थी। फिर भी यह हमला क्यों हुआ ? यह देखने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे देश में दुर्भाग्य से जनता को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया ही बन्द है। जब कोई एकाध घटना हो जाती है तो उसके ऊपर नेताओं के वक्तव्य आ जाते हैं। मूल में क्या है, यह खोजने की कोशिश नहीं होती। आर्थिक क्षेत्र में तरह–तरह की घटनाएँ होती हैं। एक घटना हो गयी एक वक्तव्य आ गया। उदाहरण के लिए हिन्दुस्थान में पिछले साल ३६.६ लाख टन

गेहूँ का उत्पादन हुआ, तो भी अमेरिका से १५ लाख टन गेहूँ क्यों मँगाया गया ? एक अलग घटना समझकर १०–५ नेताओं ने वक्तव्य दे दिये। सारी दुनिया में पेट्रो प्रोडक्ट्स की कीमत जब गिरती जा रही थी उस समय हिन्दुस्थान में पेट्रो प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई गयी जिसमें मिट्टी का तेल, जो गरीब आदमी का है– वह भी शामिल है। एक केवल वक्तव्य आ गया, कि यह नहीं बढ़ाना चाहिए था, १०–५ नेताओं ने वक्तव्य दे दिये, वास्तव में जितनी घटनाएँ आर्थिक क्षेत्र की हैं, यह देखने में अलग–अलग दिखती होंगी लेकिन इन सबके पीछे एक सूत्र है। जैसे किसी को बार–बार फोड़ा–फुन्सी होती है, एक जगह फोड़े की मलहम पट्टी की, अच्छा नहीं होता, दूसरी जगह फिर फोड़ा होता है तो मूल में जाने की आवश्यकता है कि कहीं खून की खराबी तो नहीं है। अगर खून की खराबी है तो खून कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी दवा देने की आवश्यकता है केवल मरहम पट्टी से काम निकलने वाला नहीं। वैसे ही जो अलग–अलग घटनाएँ दिखाई देती हैं, उस सबके पीछे कोई सूत्र है, यह देखने की आवश्यकता है। वरना हम एक–एक घटना का विरोध करते रहेंगे, इसका कोई अन्त नहीं होगा।

दो परिस्थितियाँ

जब हम ऐसा देखते हैं तो दिखेगा कि दो परिस्थितियों के संयोग के कारण आज की आर्थिक दुरावस्था निर्माण हुई है। यह दो परिस्थितियाँ क्या हैं ? एक बाह्य परिस्थिति है, एक अन्तर्गत परिस्थिति है।

साम्राज्यवादी देशों के मंसूबे

बाह्य परिस्थिति क्या है ? १९४७ में हमें स्वातन्त्र्य मिला, किन्तु केवल अकेले हिन्दुस्थान को ही स्वातन्त्र्य मिला ऐसी बात नहीं। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के दबाव के कारण उस समय के सफेद साम्राज्यवादी देशों को बाध्य होकर अपने–अपने उपनिवेशों को स्वतन्त्रता देनी पड़ी, इस कारण कई देशों को दूसरे महायुद्ध के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है लेकिन यह जो सारे सफेद साम्राज्यवाद देश थे, उनका अपने–अपने देश का आर्थिक ढाँचा स्वावलम्बी नहीं था। वे देश बहुत समृद्ध हैं ऐसा किसी का ख्याल ही है। वास्तव में उनकी समृद्धि का आधार उपनिवेशों का शोषण था। जैसे हिन्दुस्थान से सस्ता कच्चा माल इंग्लैण्ड ले जाना, वहाँ पक्का माल निर्माण कर

हिन्दुस्थान में निर्मित माल ज्यादा रेट में बेचना। हिन्दुस्थान उनकी कालोनी होने के कारण रेडी मार्केट के रूप में उनके लिए उपलब्ध था। जैसा इंग्लैण्ड हमारा शोषण करता था वैसे ही सफेद साम्राज्यवादी देश अपनी कालोनियों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब परिस्थिति के दबाव के कारण स्वतन्त्रता तो देनी पड़ी लेकिन उनका आर्थिक ढाँचा तो परावलम्बी था। अब अगर यह आर्थिक शोषण अन्य देशों का बन्द हो जाता है तो उनका आर्थिक ढाँचा टूट जायेगा ऐसी परिस्थिति है, इसके कारण वे इस फिकर में हैं कि किस तरह से आज की स्थिति में भी अपना आर्थिक साम्राज्य, इन सभी नवस्वतन्त्र, अर्द्धविकसित देशों में फैलाया जाये, इस चिन्ता में यह सारे देश हैं।

श्वेत राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य–निर्माण के प्रयास

आज जिस तरह से दुनिया का प्रचलित नक्शा है, इसमें इत्तिफाक से, जितने विकसित पुराने साम्राज्यवादी देश हैं यह सभी उत्तर में आ रहे हैं और यह जो नवस्वतन्त्र अविकसित देश हैं, वे सारे दक्षिण में आते हैं। इसके कारण आज नई परिभाषा चल पड़ी है, उत्तरी देश व दक्षिण देश। यह सारे उत्तरी देश इस चिन्ता में हैं कि दक्षिणी देशों का आर्थिक शोषण करते हुए अपने आर्थिक साम्राज्य का गढ़ किस तरह निर्माण किया जाए। इस चक्कर में ये सारे देश हैं किन्तु रूस को जो सुविधा उपलब्ध है, वह सुविधा इन देशों को उपलब्ध नहीं है। रूस का भी आर्थिक ढाँचा व समृद्धि स्वावलम्बी नहीं है लेकिन रूस को जितना आर्थिक शोषण करना है वे सभी छोटे–छोटे पूर्व यूरोपीय देश, पूर्व जर्मनी, बलगारिया, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि सारे रूस के बिल्कुल बगल में हैं। देश छोटे हैं अतः प्रतिकार नहीं कर सकते क्योंकि रूसी टैंक की छाया में हैं। कभी भी गड़बड़ करेंगे तो रूसी सेना खटाक से घुस सकती है इसके कारण उनकी हिम्मत नहीं हो सकती। इस तरह बगल में ही छोटे–छोटे देशों का शोषण करने की जो सुविधा रूस को है, वह इन सफेद साम्राज्यवादी देशों को नहीं है इसके कारण नवस्वतन्त्र अविकसित देशों में, अपना आर्थिक साम्राज्य निर्माण करने की दृष्टि से उनको तरह–तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए उनको आवश्यक हो जाता है कि इन देशों में ऐसी सरकारें स्थापित होनी चाहिए जो सरकारें अपनी जनता का शोषण करने की खुली छूट, अपनी जनता का हर तरह से नाजायज फायदा उठाने की खुली छूट साम्राज्यवादी देशों को दे दें। इस तरह की जनता–विरोधी सरकारें इन सब

नवस्वतन्त्र देशों में स्थापित कराना उनको आवश्यक है। अगर सरकारें राष्ट्रभक्त होंगी और सोचेंगी कि हम अपने देश में किसी का आर्थिक साम्राज्य नहीं आने देंगे तो उन देशों का आर्थिक ढाँचा टूट जायेगा, वह गरीब हो जायेंगे ऐसी आज की हालत है। इस दृष्टि से अपने आर्थिक साम्राज्य के अड्डे सभी नवस्वतन्त्र देशों में स्थापित करने के लिए, जनता विरोधी एवं राष्ट्रीयता विरोधी सरकारें सभी नवस्वतन्त्र देशों में लाने का प्रयास उन साम्राज्यवादी देशों का है, वह उनकी आवश्यकता है– यह एक बाह्य परिस्थिति है।

आज राजनैतिक ढाँचा देश के उपयुक्त नहीं

अब अन्तर्गत परिस्थिति क्या है ? हम जानते हैं कि हमारे देश में एक राजनैतिक ढाँचा है, एक संविधान है। इस संविधान के विषय में प्रारम्भ से ही कहा गया था कि यह इस भूमि की उपज नहीं है, पश्चिम से वैसे के वैसे उठाकर यहाँ लाया गया है। अतः यह देश के लिए उपयुक्त नहीं होगा, यह बात राष्ट्रभक्त विचारकों ने प्रारम्भ से कही थी। पूज्य महात्मा जी ने १९१५–१६ में एक छोटी–सी किताब लिखी 'हिन्द स्वराज्य', उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे देश में ब्रिटिश पार्लामेन्ट्री सिस्टेम ठीक नहीं चलेगी और अगर हम जबदस्ती थोप देते हैं तो उसके घोर दुष्परिणाम होंगे। लोगों की हालत कैसी होगी उनके शब्द थे "एक वेश्या के समान जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है।" ऐसी लोगों की अवस्था हो जायेगी ऐसा उन्होंने लिखा था। पिछले ४ साल का इतिहास देखें तो गांधी जी ने कितनी दूरदर्शिता की बात कही, इसका हमें अंदाजा आ सकता है। लेनिन के साथ जिन्होंने काम किया, लेकिन बाद में स्वतन्त्र विचारक होने के कारण जो कम्युनिज्म के ऊपर उठकर अपने देश का विचार करने लगे– ऐसे एम.एन. राय ने कहा कि इस प्रकार की पद्धति हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं होगी। बाबू जयप्रकाश नारायण और विनोबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है। पोलिटिकल पार्टी की पद्धति यहाँ ठीक नहीं चल सकेगी। योगी अरविन्द ने स्पष्ट रूप से कहा– और काफी पहले कहा कि पोलिटिकल पार्टी सिस्टेम वह हिन्दुस्थान के लिए विदेशी पद्धति है, वह यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकती। परमपूजनीय श्री गुरुजी ने कहा कि आज की जो पद्धति है वह पद्धति उपयुक्त नहीं, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए, फंक्शनल रिप्रेजेन्टेशन लाना चाहिए। ऐसे तरह–तरह के सुझाव उन्होंने दिये। यानी जो विचारक राष्ट्रभक्त हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि यह

पद्धति हमारे देश के लिए घातक है।

कारण स्पष्ट है-- आप देखिये कि यह देश कितना गरीब है। ६० प्रतिशत लोग दलित रेखा के नीचे हैं और ४२ करोड़ लोग निरक्षर हैं, १२ करोड़ लोग केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं, वह लिखना–पढ़ना नहीं जानते। जिस देश में गरीबी व निरक्षरता इतनी भीषण हो उस देश में आज की पद्धति में, जो जल्दबाजी में सरकार बनाना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि अपने एम.पी. व एम.एल.ए. को ज्यादा संख्या में चुनकर ले आये और एम.पी. व एम.एल.ए. को जहाँ गरीबी व निरक्षरता इतनी भीषण है ज्यादा संख्या में अगर चुनकर लाना है तो आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार लाया जाये, पैसा बहाया जाये, तभी आज की स्थिति में ज्यादा लोगों को चुनकर लाना सम्भव हो सकता है।

ध्येयवादी राजनीतिक के लिए धैर्य चाहिए

एक व्यक्ति ने राजनीति की यह परिभाषा की, उन्होंने हालाँकि मजाक में ही कहा किन्तु बात सत्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति एक सौम्य कला है-- गरीब जनता से वोट प्राप्त करने की, इलेक्शन का धन श्रीमान लोगों से लेकर दोनों को बताने की कि हम एक से दूसरे का संरक्षण करेंगे। गरीबों से वोट और अमीरों से नोट प्राप्त करना– यह सौम्य कला यानी राजनीति है। यह बात आज बिल्कुल सही है और इसके कारण यदि हमारे में से ऐसा कोई ध्येयवादी राजनीतिक दल हो, जो सोचेगा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, राष्ट्रीय चेतना का स्तर सार्वजनिक शिक्षा का स्तर लगातार ऊँचा उठाने की कोशिश करेंगे, देश लम्बा–चौड़ा होने के कारण जनता विशाल होने के कारण सम्पूर्ण जनता में राष्ट्रीय चेतना का व शिक्षा का स्तर ऊँचा करने में हो सकता है कि हमें २५–३० साल लगें तो भी चलेगा– किन्तु हम साधन शुचिता छोड़ने वाले नहीं– शिक्षा का स्तर ऊँचा हो जायेगा, इस तरह की राष्ट्रीय चेतनायुक्त जनता हमें सत्ता में लायेगी, तब तक हम निरपेक्ष बुद्धि से काम करते रहेंगे, चाहे २५ साल लगे चाहे ३० साल लगे, इस तरह का धीरज रखने वाला जो राजनैतिक दल होगा, वही केवल साधन शुचिता को कायम रख सकता है।

जिन्हें सत्ता में आने की जल्दबाजी हो गयी है उनके लिए अपरिहार्य है कि उन्हें भ्रष्टाचार करना चाहिए, वोट खरीदना चाहिए और वोट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा, पैसा वाले से ही आता है, गरीब लोगों से पैसा नहीं

आता और पेसे वाला यदि पैसा देगा, वह राजा कर्ण नहीं है, शिवि नहीं, युधिष्ठिर नहीं है– हर्षवर्धन नहीं है जो कहेगा कि आओ, मेरा खजाना लूट कर ले जाओ, किन्तु यहाँ तो एक–एक पैसे के पीछे शर्त होगी। पैसे वाला यदि पैसा देता है उसके पीछे शर्त है, कि मेरे निहित स्वार्थ का, संवर्धन व रक्षण होगा। आज अपने व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थ के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान को बेचने के लिए तैयार, ऐसे लोग चौराहे पर खड़े हैं जो धीरज नहीं रख सकते कुछ साल तक जिनकी धैर्य से काम करने की इच्छा नहीं है, जो तुरन्त कुछ न कुछ तिकड़मबाजी कर सत्ता में आना चाहते हैं और इसलिए जो काला पैसा प्राप्त करना चाहते हैं वे एक तरफ चौराहे पर खड़े है– राह देख रहे हैं कि मैं इतनी लम्बी देर तक यहाँ चौराहे पर खड़ा हूँ मुझे खरीदने के लिए अभी तक कोई क्यों नहीं आ रहा है, इस चिन्ता में वे वहाँ पर खड़े हैं।

विदेशी षड्यन्त्रों से जनता विरोधी सरकारें

जो बाह्य परिस्थिति मैंने बतायी कि हमारे देश में और अन्य नवस्वतन्त्र देशों में, अपने आर्थिक साम्राज्य के अड्डे निर्माण करने के हेतु जहाँ जनता विरोधी सरकारें जो आर्थिक शोषण अपनी जनता का करने देंगी इस तरह की जनता विरोधी सरकारें, हमारे देश में व अन्य देशों में लाने के लिए, चाहे जितना पैसा करने की जिनकी तैयारी है, ऐसे कुछ विदेशी सरमायेदार और कुछ विदेशी सरकारें बाहर खड़ी है और इधर यह अपने को बेचने के लिए तैयार हैं, वह उधर खरीदने के लिए तैयार हैं। दोनों परिस्थितियों का संयोग होकर, आज की आर्थिक संकट परम्परा निर्माण हुई है। इस बात पर हमको गहराई से सोचना चाहिए। दुःख की बात है कि विदेशी सरमायेदार, इनका साथ देने के लिए, यह जो सत्ता के लालच में, धीरज न रखते हुए, चाहे जो शर्तें स्वीकार करते हुए सत्ता में आने की जहाँ नेताओं की तैयारी है वैसे ही अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए, राष्ट्र की आर्थिक स्वतन्त्रता को गिरवी रखते हुए, विदेशी सरमायेदारों का साथ देने के लिए, हमारे यहाँ के एकाधिकारी पूँजीपति तैयार हुए हैं– यह हमारे लिए अत्यन्त लज्जा की बात है।

मैं सभी सरमायेदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि छोटे और मध्यम सरमायेदारों का हिसाब ही नहीं है। जो बड़े सरमायेदार हैं– हमारे २० एकाधिकारी घर हैं, यह अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए, विदेशी सरमायेदारों का साथ दे रहे हैं और इस तरह मोनोपली सरमायेदार और भारत सरकार, चारों

का मिलकर यह षड्यन्त्र है। इस षड्यन्त्र की शर्त यह है कि उनके निहित स्वार्थ का संवर्धन व संरक्षण होगा और यह संवर्धन व संरक्षण यदि करना है, तो हिन्दुस्थान की गरीब जनता को कुचले बगैर, हिन्दुस्थान की गरीब जनता का शोषण किये बगैर उनके निहित स्वार्थों का संरक्षण व संवर्धन नहीं हो सकता और इसलिए, उन लोगों को जो आश्वासन दिये हैं उन आश्वासनों की पूर्ति करने के लिए, गरीब जनता पर हमला करने की पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। उसी का प्रतीक परिचायक यह बात है कि हड़ताल का अधिकार छीन लेने वाला कानून सरकार लायी है।

मजदूर संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन

भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है। हम यह नहीं चाहते कि उत्पादन में बाधा आये किन्तु औद्योगिक शांति, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ मजदूरों की नहीं हो सकती। अपने–अपने स्वार्थ के लिए मालिक, मैनेजमेंट सरकार, सरकार के अफसर, ये यदि गैर जिम्मेवारी का व्यवहार करते हैं, मजदूरों की न्याय्य माँगें मानने से इनकार करते हैं, तो फिर जायज माँगें मनवाने के लिए अन्तिम शस्त्र के रूप में हड़ताल करने का अधिकार मजदूरों को होना ही चाहिए, यह नीति भारतीय मजदूर संघ की है। जैसे काम करने के अधिकार को, मौलिक अधिकारों की सूची में डाला जाना चाहिए वैसे ही हड़ताल करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकारों की सूची में डाला जाना चाहिए। यह प्रारम्भ से हम लोगों ने कहा है। हाँ राष्ट्रभक्ति के कारण हम यह चाहते हैं, कि हड़ताल का लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेने का सरकार को अधिकार नहीं लेकिन ऐसी कानूनी मशीनरी बनानी चाहिए, जिसके कारण मजदूरों में यह विश्वास निर्माण हो कि हड़ताल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी उचित बातें इस मशीनरी के कारण पूरी हो सकती हैं। किस तरह की मशीनरी बन सकती है, इसके ठोस सुझाव भारतीय मजदूर संघ ने समय–समय पर दिये हैं।

हड़ताल का अधिकार छीनना लोकतंत्र विरोधी

हड़ताल का लोकतांत्रिक अधिकार मजदूरों से छीन लेना यह मजदूर विरोधी व लोकतन्त्र विरोधी बात है। इस बात को भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह जो हमला हुआ है इसका प्रमुख कारण विदेशी सरमायेदार, कुछ विदेशी सरकारें, हमारे एकाधिकारी पूँजीपति भारत सरकार व इनका

गरीब–विरोधी और जनतंत्र–विरोधी साझा मोर्चा बनना है। यह संयुक्त मोर्चा बना है उसके कारण यह हमला हो रहा है। क्योंकि वे जानते थे कि जब गरीबों का शोषण शुरू होगा, देश के चारों ओर फैला हुआ गाँवों का कारीगर असंगठित है, क्या खेतिहर मजदूर, क्या गाँव में फैले हुए बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार बेचारे असंगठित हैं, प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार तो यह शहर का औद्योगिक मजदूर करेगा, इसकी कमर यदि तोड़ दी जाती है, तो बाकी लोगों का शोषण हम आराम से कर सकते हैं, कोई आवाज नहीं उठायेगा यह समझकर संगठित मजदूरों पर यह हमला हुआ है।

तानाशाही कायम करने की नयी रणनीति

यह हमला सिर्फ संगठित मजदूरों पर है ऐसा अगर किसी का ख्याल होगा तो वह गलत बात है। यह जो संयुक्त मोर्चा है; सरमायेदारों व सरकार का, इसका आगे चलकर क्या मतलब होता है यह भी देखना चाहिए। जून १६७५ में तानाशाही लाने का प्रयास हुआ, क्यों हुआ ? कारण स्पष्ट है। गरीब विरोधी नीतियों को लेकर यदि सरकार चलती है, सरकार के पास प्रचार तंत्र अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा देर तक जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। गरीब लोग नेताओं का सच्चा स्वरूप समझ जायेंगे और यदि उस अवस्था में लोकतंत्र कायम रहता है और चुनाव होते हैं, तो आज के सरकारी दल को फिर से चुनकर लाना, असंभव हो जायेगा। इस दृष्टि से यह सोचा गया कि लोकतंत्र को समाप्त करते हुए तानाशाही लानी चाहिए। ताकि अपने व्यक्तिगत पारिवारिक स्वार्थ सिद्ध होते रह सकें, चुनाव का झंझट नहीं, तानाशाही कायम हो जायेगी। विदेशी व देशी सरमायेदारों का लाभ होता रहेगा और भारत सरकार की अपनी कुर्सी बनी रहेगी। सन् ७५ में यह विचार था और आज भी यह विचार है। लकिन जून, १६७५ में जो गलतियाँ की थीं, उनको न दोहराने का विचार सरकार ने किया है। उस समय की सबसे बड़ी गलती यह थी कि एकदम आपातकाल लाया गया। इसके कारण इकट्ठे एक ही समय सबको दुश्मन बनाया गया और इसके दुष्परिणाम १६ महीने के बाद उनको भुगतने पड़े। इस गलती को दोबारा न दुहराने का विचार सरकार ने किया है। यह नयी रणनीति सरकार ने ली है।

यह रणनीति है एक–एक को पकड़ कर उसकी पिटाई करना और तब तक बाकी जनता को समझाना कि यह बदमाश था, गड़बड़ कर रहा था

इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। आप से हमारी दोस्ती है, आपके खिलाफ कुछ नहीं है। ऐसा बाकी लोगों को शान्त रखना। एक की पिटाई हो जायेगी, फिर दूसरे को पिटाई के लिए पकड़ना– इस तरह एक–एक को पकड़ के पिटाई करना यह रणनीति सरकार ने अपनाई है और इसमें पहला नम्बर संगठित मजदूरों का आया हुआ है।

दूसरी बारी प्रेस की

यह आखिरी नम्बर नहीं है, मजदूर यदि इस लड़ाई में हार जाते हैं। मजदूर–आन्दोलन की कमर अगर टूट जाती है तो दूसरा नम्बर प्रेस का आने वाला है, यह बात मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ। आगे नम्बर आने वाला है, इतनी ही बात नहीं, आज समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होता, किन्तु मैं जानता हूँ कि जो बड़े राष्ट्रीय वृत्त पत्र हैं, जिनकी खपत बहुत बड़ी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस कारण सरकार के खिलाफ टीका–टिप्पणी करने का साहस जो रख सकते हैं ऐसे बड़े राष्ट्रीय वृत्त पत्रों के अन्तर्गत कारोबार में हस्तक्षेप करते हुए गड़बड़ निर्माण करने का प्रयास आज भी अप्रत्यक्ष अपने एजेण्टों के द्वारा सरकार ने किया है। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जब मजदूर आन्दोलन की कमर टूट जायेगी, दूसरा नम्बर वृत्त पत्रों का आयेगा और वह खत्म हो जायेगा।

तीसरा प्रहार अन्य लोकतान्त्रिक शक्तियों पर होगा

तीसरा नम्बर सभी प्रकार की लोकतांत्रिक शक्तियों का आयेगा। इस तरह एक–एक कर पकड़ कर पिटाई करना, यह नई रणनीति सरकार ने तय की है। इस लड़ाई में मजदूरों की पिटाई हो रही है। लोकतन्त्र की समर्थक शक्तियाँ यदि जागरूक न रहीं, इस लड़ाई का सच्चा स्वरूप उन्होंने नहीं समझा और मजदूरों की यदि हार हो जाती है तो लोकतान्त्रिक शक्तियों को बहुत बड़ी चोट पहुँचने वाली है। किन्तु यदि इस लड़ाई में मजदूरों की विजय होती है तो तानाशाही लाने वाली शक्तियों को बड़ी चोट पहुँचने वाली है। यह लड़ाई यद्यपि बाहर से दीखने के लिए केवल मजदूरों की अपने अधिकारों की लड़ाई होगी वास्तव में यह एक शृंखला की कड़ी है।

सरकार द्वारा मजदूरों पर आक्रमण तानाशाही–शृंखला की एक कड़ी

सरकार का यह आक्रमण अकेली घटना नहीं– एक शृंखला की पहली

कड़ी है और इसमें यदि मजदूर हार जाता है तो स्वतन्त्रता को धक्का लगेगा। यह मजदूर की लड़ाई केवल मजदूर के हड़ताल के अधिकार की लड़ाई नहीं तो लोकतन्त्र को बचाने की लड़ाई है यह बात सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को समझना चाहिए। हमारे इधर एक कहावत है कि महिलाएँ सुबह के समय जब अनाज के दाने पीसने के लिए बैठती हैं तो कुछ अनाज के दाने चक्की में चले जाते हैं और कुछ अनाज के दाने बाहर किसी महिला के हाथ सूप में आनन्द से नाचते रहते हैं। यह जो सूप में आनन्द से नाचने वाले अनाज के दाने हैं यह चक्की में जो दाने गये हैं उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, इनकी अच्छी पिसाई हो रही है, होने दो, लेकिन वे नहीं जानते कि दस मिनट बाद उनका भी नम्बर आने वाला है उनको भी चक्की में डाला जायेगा। उनकी वैसे ही पिसाई होगी जैसी आज इनकी हो रही है।

केवल श्रमिकों की नहीं तो यह 'लोकतन्त्र बचाओ' की लड़ाई है

सरकारी प्रचार के कारण लोकतन्त्र के समर्थक लोग भी ऐसा मान रहे हैं कि यह तो मजदूरों की लड़ाई है हमें इसमें लेना–देना क्या है ? किन्तु वे नहीं जानते कि यदि इसमें मजदूरों की पिसाई पूरी तरह से हो गयी, तो अगला नम्बर तुम्हारा भी आने वाला है– लोकतन्त्र के समर्थक लोग इस बात को कभी जानते नहीं हैं। यदि उन्होंने यह जागरूकता नहीं रखी और इस लड़ाई में मजदूर आन्दोलन का पूरा समर्थन नहीं किया, मजदूर हार जायेगा इतनी ही बात नहीं तो लोकतंत्र को समाप्त करने के प्रयास में तानाशाही लाने के प्रयास में भारत सरकार को बहुत बड़ा समर्थन व शक्ति प्राप्त होगी। यह बात सोच–समझकर सभी लोकतन्त्र के समर्थकों को ध्यान में रखनी चाहिए और यह लड़ाई केवल मजदूरों के अधिकार की लड़ाई नहीं, यह 'लोकतंत्र बचाओ' की लड़ाई है, यह समझकर इस लड़ाई में मजदूरों का पूरी ताकत से समर्थन करना चाहिए।

संकट परम्परा का मूल कारण : स्वाभिमान शून्यता

वैसे ही इस संकट परम्परा का मूल कारण क्या है इसका विचार सभी राष्ट्रभक्त लोगों को करने की आवश्यकता है। मैं केवल मजदूर क्षेत्र तक सीमित बात नहीं कर रहा। आज चारों ओर एक निराशा का वायुमण्डल है। सभी देशभक्त सोच रहे हैं कि क्या होगा ? ३४ साल तक हम कुछ बना नहीं पाये, हमारी तो एक के बाद एक अधोगति होती जा रही है। मालूम होता है कि हमारे

अन्दर यह क्षमता ही नहीं है जिसके आधार पर देश को ऊपर लाया जा सकता है। इस तरह की आत्मग्लानि का विचार देशभक्त लोगों के मनों में निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं कि दूसरा महायुद्ध, जर्मनी व जापान की भूमि पर लड़ा गया था, इसके कारण वे देश उद्ध्वस्त हो गये थे, लेकिन इतने थोड़े समय में दोनों ने अपने राष्ट्र का इतना निर्माण किया कि आज जर्मनी की दहशत सारे यूरोप पर है और आर्थिक दृष्टि से जापान का येन अमेरिका के डालर को धक्का दे रहा है– इतनी प्रगति दोनों देशों ने की। हमारे देश में तो महायुद्ध लड़ा नहीं गया था, तो भी हम नीचे जा रहे हैं। लोगों के मन में यह भ्रम है कि हम नीचे जा रहे हैं इसका कारण ऊपर उठने की हमारी क्षमता नहीं और इसलिए अब आशा के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इस प्रकार का विचार सर्वसाधारण नागरिक के मन में आ रहा है। बात बिल्कुल गलत है। हमारे देश में वह सारी क्षमताएँ हैं जिसके आधार पर किसी भी राष्ट्र को दुनियाँ का एक महान् राष्ट्र बनाया जा सकता है। हमारे पास साधनों की शक्ति है, हमारे पास मनुष्य बल है, हमारे पास वह गुणवत्ता है जिसके कारण आज पश्चिमी देश प्रगति कर रहे हैं। अमेरिका का 'नासा' जहाँ आकाशीय विज्ञान की प्रयोगशाला है वहाँ अगर आप जायेंगे तो अमेरिकन व जर्मन वैज्ञानिक व टेक्नालॉजिस्ट के कंधे से कंधा लगाकर हमारे भारतीय वैज्ञानिक और तन्त्रज्ञ काम कर रहे हैं और वहाँ उनको समान इज्जत दी जाती है यह आपको दिखाई देगा। हम विज्ञान में, तन्त्रज्ञान में, गुणवत्ता में कम नहीं। ऊपर आने के लिए वह सारा मसाला हमारे पास तैयार है। फिर हम नीचे क्यों जा रहे हैं ? इसका एक ही कारण है कि शासन चलाने वाले नेताओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं।

अपने पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता

हम अपने राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, यह आकांक्षा नहीं, केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए सत्ता का उपयोग करने की सीमित इच्छा है, राष्ट्र को बड़ा बनाने की इच्छा नहीं है। इसके कारण आप जानते हैं हमारे देश में जो योजनाएँ चल रही हैं वह भारतीयों द्वारा चलायी हुई योजनाएँ नहीं हैं। ऐसा दीखता होगा कि योजना आयोग के सभी सदस्य भारतीय हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन व निर्देशन सारा विदेशी विशेषज्ञ कर रहे हैं और विदेशी विशेषज्ञ अपने–अपने देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारे देश की योजनाएँ बना रहे हैं। माने हिन्दुस्थान की योजना विदेशों

की सुविधा को ध्यान में रखकर हो रही है, यह बात चारों ओर दिखाई दे रही है, हम अपने बल पर खड़े हो जायें, वैसी आज की स्थिति नहीं है।

चीन स्वावलम्बी कैसे बना ?

हमारे नजदीक चीन है उसका उदाहरण हम लेंगे। चीन के माओ जितने कम्युनिस्ट थे उतने अधिक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने किस तरह व्यवहार किया, हमारे नेता किस तरह व्यवहार करते हैं, एक छोटा–सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि १९४८ में चीन में राज्य क्रान्ति हुई, कम्युनिस्टों के हाथ में चीन की बागडोर आयी। उस समय चीन में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का वायुमण्डल था, सारी दुनिया के कम्युनिस्ट देश एक हैं, यह स्वप्न रंजन चल रहा था। रूसी चीनी भाई–भाई के नारे चल रहे थे और इस कारण जो चीन की प्रथम पंचवार्षिक योजना थी वह पूरी तरह से रूस ने तैयार की हुई थी। योजना बनाने वाले रूसी, योजना के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ सारे रूसी थे। योजना व प्रकल्प की सारी मशीनरी भी रूसी थी। उनको लगता था कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद है, वह आये क्या, हम रहे क्या–एक ही बात है, ऐसा स्वप्न रंजन चल रहा था। लेकिन धीरे–धीरे माओ के मन में यह ख्याल आया कि यह अन्तर्राष्ट्रीयता का नारा धोखा है। रूस अपना आर्थिक साम्राज्य यहाँ फैलाना चाहता है, आर्थिक शोषण करना चाहता है। यह दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, माओ और उनके साथियों में जाग्रत हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि रूस को यहाँ से हटाना है। शीतयुद्ध शुरू हुआ और १९६० में रूस व चीन का सम्बन्ध विच्छेद हो गया। जिस समय सम्बन्ध विच्छेद हुआ, उस समय रूस ने सोचा कि चीन नया राष्ट्र है इस पर दबाव लाया जा सकता है, दबाव की नीति लायी जा सकती है और इस दृष्टि से जैसे ही सम्बन्ध विच्छेद हुआ वैसे ही उन्होंने तुरन्त दबाव लाने के लिए अपनी सारी पूँजी वापस ले गये, अपने सारे विशेषज्ञों को वापस बुला लिया और अपनी सारी मशीनरी वापस ले गये, क्योंकि सारी योजना व प्रकल्प रूसी मशीनरी के सहारे चल रहे थे, अतः वे सोच रहे थे कि इसके कारण माओ दब जायेगा, झुक जायेगा और हमारी शरण में आ जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे धीरज के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ खड़े हुए। चीन की जो परम्परागत पद्धतियाँ व योजनाएँ थीं उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, लोक समझ सकें इतनी तकनीकी जानकारी देते हुए उन परम्परागत योजनाओं को बढ़ावा दिया। रशियन विशेषज्ञों

ने कुछ सिखाया नहीं था तो भी देख—देखकर उनके नीचे काम करने वाले चीनी लोगों को सीखना चाहिए, उस प्रक्रिया में से अपने विशेषज्ञों को 'ट्रायल एन्ड एरर' पद्धति से अपने प्रकल्पों को चलाने की इजाजत दी। अपने वैज्ञानिकों और अपने तकनीकियों के भरोसे देश का निर्माण करने का प्रयास किया।

एक उदाहरण

आज हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान—शून्य सरकारी नौकर किस तरह काम कर रहे हैं— एक छोटा उदाहरण तुलनात्मक विवेचन के लिए आपके ख्याल में आ जाये इसलिए मैं देना चाहता हूँ। अभी कलकत्ता के पास हुगली नदी पर दूसरा पुल बनाने का कार्य चल रहा है। वास्तव में यह पुल बनाने के लिए जिस—जिस कौशल्य की आवश्यकता है वह सारा कौशल्य हमारे देश में है। जो योजना कर सकते, ब्ल्यूप्रिंट बना सकते ऐसे सभी भारतीय इंजीनियर व तकनीकी हमारे पास हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि प्रकल्प मसविदा वृत्त तैयार करने से लेकर अब तक हमारे किसी इंजीनियर को उसमें नहीं लिया गया न हमारे विशेषज्ञ की सहायता ली गयी। विदेशी विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीकी आये और उनके नीचे काम करने का कार्य भारतीयों को बताया जा रहा है। इसकी तुलना में दूसरा उदाहरण देखिये। १९६० में जब यह दिखाई देने लगा कि अब रूस से सम्बन्ध विच्छेद होगा, उसके एक डेढ़ साल पहले वहाँ की एक बड़ी नदी यांगसी पर पुल बनाने का कार्य चल रहा था। रूसी मशीनरी थी रूसी विशेषज्ञ थे। थोड़े दिन की बातचीत के बाद सरकार ने उनको बताया कि महाराज, आप सब लोगों को हम दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, वहाँ बड़ा जरूरी काम है। आपके बिना हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम जायेंगे तो इस पुल का काम अधूरा रहेगा, सरकार ने कहा कि इसे अधूरा रहने दीजिए वहाँ ज्यादा जरूरी काम है। सारी फौज रूसी विशेषज्ञों की वहाँ भेजी गयी। कुछ महीनों के बाद उनको दोबारा यहाँ लाया गया। उनको आश्चर्य हुआ कि पुल का कार्य पूरा हो गया है। सरकार ने पूछा कि आपके जो स्पेसीफिकेशंस थे, उसमें और जो पुल तैयार हुआ है उसमें कितना अन्तर है। उन्होंने खोज कर निकाला केवल १.५ सेंटीमीटर का अन्तर था। रूसी विशेषज्ञों ने चीनी विशेषज्ञों को कुछ सिखाया नहीं था, बे केवल अनुभव के आधार पर सीखे, केवल १.५ सेटीमीटर का अन्तर था। उसके बाद उनको आश्चर्य का धक्का देनें वाली एक घटना हुई। उनको एक दूसरे स्थान पर ले गये। पुल बनाने की जो रूसी

मशीनरी थी ऐसे दो सेट वहाँ रखे गये थे। उनको बताया गया कि इसमें एक सेट आपका है एक सेट हमने तैयार किया है आपका सेट कौन सा है और हमारा सेट कौन सा है यह जरा पहचान लीजिए, वह पहचान नहीं सके। जब यह सारे विशेषज्ञ दूसरी जगह गये थे– बीच की कालावधि में इस माडेल की पूरी नकल इतने अच्छे ढंग से उन्होंने की, वह पहचान नहीं सके कि इसमें रूसी मशीनरी कौन सी है और चीनी मशीनरी कौन सी है।

यह महान् प्रयास इस तरह का जगह–जगह जो किया इसके कारण उन्होंने अपने राष्ट्र के सामने राष्ट्रीय स्वाभिमान की घोषणा रखी। केवल भाषण में घोषणा नहीं की। क्या राष्ट्रीय स्वावलम्बन का कुछ भी मतलब हो सकता है अगर विदेशों से गेहूँ लाकर यहाँ खाया जाये। उन्होंने यह एक लक्ष्य रखा कि हमारा राष्ट्रीय पुनः उत्थान हमारे ही प्रयासों के आधार पर होगा, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की घोषणा उन्होंने की। एक महान् प्रयास करते हुए हम देखते हैं कि चीन में उनका राज्य हमारे बाद आया, जैसा मैंने कहा कि माओ जितना कम्युनिस्ट था उससे अधिक कट्टर राष्ट्र भक्त था, राष्ट्रभक्ति के आधार पर महान् प्रयास करते हुए आज चीन हमसे आगे निकल गया, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

राष्ट्रीय स्वावलम्बन का निश्चय करें

यदि हमने प्रयास किया होता, उसमें हम असफल होते तब तो निराशा की बात थी। इस दिशा में हमने प्रयास ही नहीं किया। हम तो दुनिया को शान्ति देने के लिए निकले और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के लिए हिन्दुस्थान की आर्थिक स्वतन्त्रता, हिन्दुस्थान का सार्वभौमत्व, विदेशियों को बेचने में हमें कोई शरम नहीं लगी। ऐसी हमारे यहाँ के नेताओं की आज अवस्था है। माने कि आज यदि हमारी गिरावट है, वह इसके कारण नहीं कि ऊपर उठने की हमारी क्षमता नहीं। हर तरह की क्षमताएँ हमारे देश के अन्दर हैं। हम यदि राष्ट्रीय स्वाभिमान से युक्त होकर, यह निश्चय करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय पुनःउत्थान अपने ही प्रयासों के आधार पर करेंगे तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस शताब्दि के अन्त तक हमारा देश दुनिया के प्रथम श्रेणी के देश में जाकर बैठ सकता है; इतनी क्षमता हमारे देश के अन्दर है। क्षमताओं का अभाव नहीं तो इच्छाशक्ति का अभाव है। इस इच्छाशक्ति के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलकर जहाँ १९४७ में बड़ी कुर्बानी के बाद हमने

राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त किया, आज फिर से हमारी स्वतन्त्रता व सार्वभौमत्व बेचने के लिए नेता लोग तैयार हो गये हैं। इसी में से अर्थिक संकट परम्परा निर्माण हुई है; यह कार्य–कारणभाव ख्याल में रखना चाहिए। विदेशियों की सुविधा के लिए हमारी गरीब जनता पर और मजदूरों पर कुठाराघात हो रहा है यह कार्य–कारणभाव ध्यान में रखना चाहिए।

लोकतन्त्र की लड़ाई

यह यदि हम ध्यान में रखते हैं तो यह लड़ाई सरकार–विरोधी मजदूरों की लड़ाई है, यह सिर्फ मजदूरों की लड़ाई है ऐसा समझना गलत होगा। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है और इस दृष्टि से सभी राष्ट्रभक्त लोगों को इस लड़ाई में मजदूरों का समर्थन करना चाहिए। याने यह लड़ाई केवल संगठित मजदूरों की नहीं तो सम्पूर्ण गरीब जनता की है। केवल गरीब जनता की नहीं, आम जनता की है। लोकतन्त्र के समर्थकों की यह लड़ाई है। राष्ट्रभक्त शक्तियों की यह लड़ाई है। इस लड़ाई का सच्चा स्वरूप समझते हुए लोकतंत्र के सभी समर्थक राष्ट्रीय स्वाभिमान की चिन्ता करने वाले राष्ट्रभक्त–सभी लोगों ने इस संघर्ष में मजदूरों का साथ देना चाहिए। यह बात आज जनता को समझाने की आवश्यकता है।

आज के इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बोलना उचित भी नहीं होगा, आवश्यक भी नहीं होगा। किन्तु मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, लोकतन्त्र के लिए, राष्ट्र के आर्थिक स्वातन्त्र्य व सार्वभौमत्व के लिए जो बड़ा खतरा सामने दिखाई पड़ रहा है इसके कारण स्वाभाविक रूप से मन में आने वाली कुछ बातें आपके सामने रखी हैं।

❖

लोकहित प्रकाशन
लखनऊ